I am obliged to repeat it. The question put was this. There is the Ramagundam super thermal power station, which is under the N.T.P.C. Fifteen per cent of the energy is there as reserve. This has not been made available to any State in the country. I therefore, would like to know from the hon. Minister whether this reserve power will be diverted, on a temporary basis, to the State of Andhra Pradesh, which is suffering from power deficiency. Did I make myself understand, Mr. Minister?

श्री सभापति : वह यह कह रहे हैं कि रामागुंडम में एन.टी.पी.सी. की जो रिजर्वड रखी हुई है, इसके अलावा दे रहे हैं क्या?

श्री कल्याण सिंह कालवी : इसमें जो 15 परसेंट का सेंटर का कोटा है, उस बिजली को जिस तरह से सदर्न जोन में बांटा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि आंध्र प्रदेश को हम 25 प्रतिशत उसमें से बिजली दे रहे हैं, कर्नाटक को 33 प्रतिशत दे रहे हैं, केरल को 15 प्रतिशत दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: The extra is being distributed. (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: He is referring to the distribution of power. I am referring to the reserve power.

MR. CHAIRMAN: He said that the reserve is being distributed.

SHRI S. JAIPAL REDDY: No.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He is giving the figures in regard to the distribution from the total power.

SHRI S. JAIPAL REDDY: He has not understood the question. In regard to the total power produced, his answer is correct. But I am drawing his attention to the reserve power, which is to the tune of 15 per cent. Will that be diverted to Andhra Pradesh, on a temporary basis?

श्री कल्याण सिंह कालवी : सभापित महोदय, जो 15 परसेंट सेंटर के पास अनएलोकेटेड कोटा रहता है, उसी में से से इस तरह मैंने बताया।

श्री सभापति : वह तो रामागुंडम के रिजर्व का आपसे पूछ रहे हैं, जो उनके पास रिजर्व है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : उसी में से दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: I was correct.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: It is one-fourth of the 15 per cent.

श्री कल्याण सिंह कालवी : उस 15 प्रतिशत को जिस तरह से बांटा है, यह मैंने आपको बताया है।

*116† [*The questioner Prof. Soumendra Bhattacharjee) was absent. For answer vide col 47 infra*].

तेल शोधक कारखानों में तेल की हानि को कम करने के उपाय

*117. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह : अरोड़ा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तेल शोधक कारखानों में तेल शोधन की प्रक्रिया में तेल की 7 प्रतिशत हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अन्य देशों के तेल शोधक कारखानों में तेल की कितनी हानि होती है ;

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तेलशोधक कारखानों में वर्तमान हानि को कम करने के लिये सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं तथा इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

1. शोधन प्रक्रिया में गर्म करने और अनेक संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वाष्प पैदा करने के लिये कच्चे तेल के कुछ भाग को ईंधन के रूप में उपभोग किया जाता है । इस ईंधन की खपत में वाष्पीकरण, संसाधन और रख-रखाव हानियां शामिल हैं जिन्हें, ईंधन और हानि कहा जाता है और आमतौर पर इसे संसाधित कच्चे तेल के प्रतिशत के रूप में जाहिर किया जाता है ।

2. ईंधन और हानि खपत रिफाइनरी की जटिलता पर और इस बात पर कि क्या विद्युत शक्ति कम की जाती है अथवा कैप्टिव आधार पर पैदा की जा रहीं है पर निर्भर करती है । गत कुछ वर्षों के दौरान भारत में सभी रिफाइनरियों की ईंधन और हानि खपत संसाधित कच्चे तेल का कुल मिलाकर 6.5% के लगभग रही है ।

3. अन्य देशों में रिफाइनरियों में ईंधन और हानि के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

4. रिफाइनरियों में ईंधन और हानि खपत को कम करने की दृष्टि से कम कुशल दाह वाले उपस्करों को उन्नत बनाने और उनके स्थान पर उच्च कुशलता वाले उपस्करों को लगाने के लिये और हीट-स्ट्रीम से प्रि-हीट की प्राप्ति में वृद्धि करने के लिये कई स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं । 1984–85 से 1988–89 के दौरान रिफाइनरियों में क्रियान्वित की गई विभिन्न ईंधन संरक्षण योजनाओं से 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की कीमत के 250000 टन प्रतिवर्ष ईंधन की बचत की वृद्धि हुई है । आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न रिफाइनरियों में क्रियान्वयन हेतु कई परियोजनाओं का और पता लगाया गया है । अनुमान है कि इन स्कीमों के पूरा हो जाने पर 267,000 टन प्रतिवर्ष ईंधन की और बचत होगी ।

5. रिफाइनरियों में ऊर्जा जमा हानि की खपत की तीव्रता में जिसे उत्पादन प्रति इकाई जटिलता का प्रति इकाई जर्जा खपत के रूप में मापा जाता है. 1984–85 से 1989–90 की अवधि के दौरान लगभग 12% की कमी आई है ।

6. हर रिफाइनरी के लिये ईंधन और हानि के लक्ष्य सरकार द्वारा वार्षिक रूप में नियत किये जाते हैं और रिफाइनरियों के निष्पादन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I would like to compliment the hon. Minister for giving a very satisfactory answer in this case. The hon. Minister has mentioned that he does not know what is the loss in the refineries in other countries. I can say that it is 4 per cent. The loss in our country, as per the reply given in the statement, is 6.5 per cent now. Details have been given as to how they are going to reduce this loss. Would you be able to reduce the loss to 4 per cent so that you can come up to the international standards?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, in the statement which has been laid on the Table of the House. I have said: "Reliable data on fuel and loss consumption in the refineries

in other countries is not available." The hon. Member has mentioned that the loss in the refineries in other countries is 4 per cent. I cannot commit right now whether we will be able to reduce the loss to that level or not.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: You can at least say as to how much you can bring it down to. If it is net 4 per cent, how are we going to achieve economy in the 8th Plan? Will that bring down to 4 per cent, 5 per cent?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: About percentage I cannot commit right now.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Inquiry into the accident of a Dormier aircraft of Vayudoot

*103. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the inquiry ordered into the accident involving a Dormier 228 aircraft of Vayudoot which took place on the 23rd December, 1989 has still not been completed;

(b) if so, by when it is likely to be completed;

(c) whether any compensation has been paid to the next of kin of the victims; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI HARMOHAN DHAWAN): (a) and (b) Following the stay granted by the Hon'ble Bombay High Court on 6.8.90 prohibiting continuous of proceedings before the Court of Inquiry investigating the accident, the Government set up a Committee of Inquiry to inquire into the accident. The Committee of Inquiry is likely to submit its report by 30.3.91.

(c) and (d) Compensation has been paid to the families of all the deceased passengers. In addition, employment has been provided to the relatives of three of deceased passengers.

Amount due under DPEA

*104. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN:

CHOWDHARY HARI SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 398 given in the Rajya Sabha on the 2nd January, 1991 and state:

(a) whether it is a fact that for the last more than two years, huge amount is due from each company under the Drug Prices Equalisation Account;

(b) when was the amount communiated to each company and since when the amount is due from each;

(c) whether his Ministry has worked out any interest on the amount due;

(d) if so, what is the amount of interest calculated in each case and the period involved; and

(e) the action taken under provision of Section 7-A of the Essential Commodities Act, 1955 to recover the amounts as arrears of land revenue?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) and (b) A statement showing the latest amount due from various companies on a tentative basis is attached. (*See* Appendix CLVII, Annexure No. 13). The amounts were communicated to